सेंटर ऑफ़ इंडियन ट्रेड यूनियन्स

के. हेमलता
अध्यक्ष

तपन सेन, पूर्व सांसद
महासचिव

दिनांक: **28** अप्रैल **2022**

प्रेस विज्ञप्ति

एलआईसी-आईपीओ बंद करो - सीटू

सेंटर ऑफ़ इंडियन ट्रेड यूनियन्स भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) खोलने के मोदी सरकार के राष्ट्र विरोधी कदम की कड़ी निंदा करता है। यह एलआईसी के निजीकरण और इसके 29 करोड़ पॉलिसीधारकों के स्वामित्व वाली 38 लाख करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को सौंपने की दिशा में एक कदम के अलावा और कुछ नहीं है।

अपने छद्म राष्ट्रवादी रुख के बावजूद, भाजपा सरकार वैश्विक और घरेलू तथाकथित 'निवेशकों' की मांगों के आगे झुक गई है, जो इस सबसे बड़े सार्वजनिक वित्तीय संस्थान को निगलने के लिए लंबे समय से पैरवी कर रहे हैं। यह याद रखना चाहिए कि एलआईसी को भारत सरकार द्वारा 5 करोड़ रुपये के अल्प निवेश के साथ निजी बीमा कंपनियों के राष्ट्रीयकरण द्वारा बनाया गया था और आज उसने पॉलिसीधारकों का विश्वास हासिल ही नहीं किया बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी बहुत योगदान दिया है। मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार अपने कॉरपोरेट आकाओं की सेवा करने के लिए इतनी बेताब है कि उसने एलआईसी के शेयरों की बिक्री की सुविधा के लिए एलआईसी के मूल्यांकन को मनमाने ढंग से आधे से भी कम कर दिया है।

एलआईसी के कर्मचारी एलआईसी में आईपीओ का लगातार विरोध करते रहे हैं। एलआईसी के आईपीओ का विरोध करने वाले मेमोरेंडम पर पॉलिसीधारकों के साथ-साथ जाने-माने नागरिकों और समाज के सभी प्रगतिशील वर्गों सहित करोड़ों लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। इस कदम के खिलाफ देश भर में बड़े पैमाने पर अभियान चल रहे हैं, खासकर केरल जहां 'केरल यूनाइटेड टू प्रोटेक्ट एलआईसी', जिसमें सभी वर्गों के लोग शामिल हैं, आंदोलन की अगुवाई कर रहा है। सरकार का इस कदम से एलआईसी आईपीओ के लगातार विरोध के प्रति इसकी असंवेदनशीलता की बू आती है और

कुख्यात बुलडोजर संस्कृति को दर्शाता है जिसे प्रमुखता मिली है। सरकार के इस कदम के खिलाफ एलआईसी कर्मचारियों ने 4 मई को आईपीओ खोले जाने के दिन दो घंटे की वॉक आउट हड़ताल की घोषणा की है।

सीटू एलआईसी आईपीओ के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन को पूरा समर्थन देता है और आईपीओ से लड़ने वाले एलआईसी कर्मचारियों और एजेंटों के साथ एकजुटता से खड़ा है - जिसका उद्देश्य हमारे देश के इस प्रमुख संस्थान का निजीकरण करना है जो हमारे लोगों और राष्ट्र की सेवा कर रहा है।

सीटू सरकार से इस प्रक्रिया को रोकने की मांग करता है और अपने सभी सदस्यों और पूरे मजदूर वर्ग से एलआईसी आईपीओ का कड़ा विरोध करने और लाभार्थियों और लोगों को इस राष्ट्र विरोधी उपाय के खिलाफ लामबंद करने का आह्वान करता है। यह मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ एकजुट संघर्ष को मजबूत करने के अपने आह्वान को दोहराता है, जिसमें एलआईसी आईपीओ एक हिस्सा है।

जारीकर्ता

के. हेमलता, अध्यक्ष

B.T. Ranadive Bhawan, 13-A, Rouse Avenue, New Delhi - 110 002
Tel# +91 11 2322 1288 / 2322 1306 Fax# +91 11 2322 1284
Website : www.citucentre.org E.mail : citubtr@gmail.com